



**Don't Stake Money  
And You Win!**

Somewhere between the sixes and the wickets, an advertisement pops up, a celebrity grinning, telling you that depositing a hundred rupees on some gaming app could make you rich by morning...

**The Game on the  
Temple Steps**

## यूपी की भांति बंगाल में भी “बुलडोजर” का खुलकर उपयोग होने लगा है

### उपयोग की शुरुआत तितजला क्षेत्र में कल आगजनी की घटना से हुई

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। उत्तर प्रदेश की तरह ही, पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनी गई भाजपा सरकार बुलडोजर के साथ अत्यधिक सक्रिय हो गई है। नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के सीधे आदेश पर, राज्य प्रशासन ने कलकत्ता के टिलजला इलाके में एक अवैध मकान और फेक्ट्री की इमारतों को गिराने के लिए तीन बुलडोजर लगा दिये।

इस कार्रवाई की वजह टिलजला इलाके में कल लगी भीषण आग थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा, लगभग 27 अन्य लोग भी घायल हुए। नए शहरी मामलों की मंत्री, अग्निमित्रा पॉल ने घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ एक मकान में आग लगने से दो व्यक्तियों की मौत तथा तीन गंभीर रूप से घायल हुए थे। नगरीय विकास मंत्री, अग्निमित्रा पॉल मरीजों को देखने अस्पताल पहुँची तथा हॉस्पिटल की हालत देखकर मंत्री महोदय ने तत्काल अस्पताल में गंदगी हटाने के आदेश दिए। नई सरकार कोई मौका नहीं गंवाना चाहती, जिससे उसे शहरों में मीडिया का पूर्ण सहयोग मिलता रहे।

■ इसी प्रकार की घटना तोपसिया क्षेत्र में भी हुई। चमड़े (लैंडर) को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को महफूज रखने के लिए कई ऑर्डर दिए हैं, हाई कोर्ट ने।

■ कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र में आग की दुर्घटना के बाद फैक्ट्री मालिक व मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन की इजाजत पूर्व नगरीय विकास मंत्री, फिरोज हकीम के कार्यकाल में मिली थी।

■ नई सरकार ने डिटेल रिपोर्ट माँगी है, जिससे यह आंका जा सके कि राज्य में किसने इतनी भारी संख्या में गैर कानूनी तरीके से निर्माण की इजाजत हासिल की थी। नई सरकार द्वारा ऑडिट कराने के बाद, सेपटी के कायदे-कानून की अवहेलना करने वाले सभी निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए जाएंगे।

### क्या सोनिया के चैकअप के कारण टला केरल पर फैसला

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। सोनिया गांधी के बुधवार को यहाँ स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल चले जाने के कारण कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री के चयन में और विलम्ब हो गया। हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार, घोषणा संभवतः बुधवार रात तक की जा सकती है।

इस विलम्ब के कारण दो मुख्य दावेदारों, एआईसीसी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन को असमंजस की

■ सोनिया गांधी काफ़ी समय से अस्वस्थ हैं और बुधवार को उन्हें स्वास्थ्य जाँच के लिए अस्पताल जाना पड़ा था।

स्थिति यथावत बनी हुई है।

राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को बैठक कर वेणुगोपाल पर फैसला अंतिम रूप देने की कोशिश की। पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, अजय माकन और मुकुल वासनिक, के अनुसार, अधिकांश पार्टी विधायक भी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं।

यह कदम मंगलवार को राहुल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## असम में समान नागरिक संहिता लागू होगी

### नवनिर्वाचित मु.मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी दी

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। गंगोत्री से गंगासागर का लक्ष्य पूरा होने के बाद, भाजपा के अब नए क्षेत्र में यूनियन सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज राज्य की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन एक शर्त के साथ, कि जनजातीय आबादी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगी। देर-सवेर पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी की सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने 19 अप्रैल को एक चुनाव रैली में स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के छह महीनों के भीतर बंगाल में यूसीसी लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा था, “बंगाल में यूसीसी इसलिए लागू किया जाएगा, ताकि राज्य के सभी नागरिकों पर एक समान, कानून लागू हो।”

उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी बिल 26 मई को विधानसभा

■ उन्होंने स्पष्ट किया कि असम के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

■ चर्चा है कि इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद शुरू होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी, भाजपा की सरकार बनने के 6 माह बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

■ उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य होगा, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी।

और कई भाजपा शासित राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समान कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। गोवा ऐसा सबसे पुराना राज्य है, जहाँ यूसीसी का एक रूप 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू था, जो 1962 में गोवा के भारतीय संघ में विलय के बाद जारी रहा। लेकिन पूरे देश में यूसीसी लागू करने की दिशा में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में यूसीसी बिल 26 मई को विधानसभा

में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल को असम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया है। सरमा ने कहा, “हमने जनजातीय आबादी को पूरी तरह यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। असम के जनजातीय समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएँ और प्रथाएँ यूसीसी के दायरे में नहीं आएंगी।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया: “यूसीसी में उत्तराधिकार, विवाह, विधवा-इन् रिलेशनशिप और विवाह तथा तलाक के अनिवार्य पंजीकरण आदि शामिल होंगे।

## आखिर कौन है शुभम खैरनार, जिसने नीट पेपर लीक किया?

### नासिक का शुभम बीएएमएस (सर्जरी) का छात्र है, उसने पुणे में किसी संदिग्ध से पेपर खरीदा और हरियाणा में किसी अन्य को बेच दिया

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए.) ने मंगलवार को 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिये हुई नीट यू.जी. 2026 परीक्षा रद्द कर दी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। खबर है कि यह घोटाला महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ, जहाँ परीक्षा की पहली डिजिटल कॉपी सामने आई।

सूत्रों के अनुसार, नासिक निवासी शुभम खैरनार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हिरासत में लिया, आरोप है कि उसने लीक हुए पेपर को पुणे के एक संदिग्ध से खरीदा और बाद में इसे 5 लाख रुपये के प्रॉफिट मार्जिन में बेच दिया।

महाराष्ट्र के बाद, लीक हुआ पेपर कथित रूप से कई राज्यों तक फैल गया, जिनमें हरियाणा के गुडगांव, राजस्थान

■ शुभम खैरनार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, बताया जाता है कि शुभम ने दस लाख रूपए में पेपर खरीदा था और उसे हरियाणा में 15 लाख रूपए में बेच दिया था।

के जयपुर और सीकर, जो एक बड़ा कोचिंग हब है, के साथ ही, जम्मू-कश्मीर, बिहार और केरल शामिल हैं। नासिक के इंदिरा नगर इलाके का 30 वर्षीय शुभम खैरनार, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.) का छात्र है। कथित तौर पर उसने पुणे के एक संदिग्ध से नीट यूजी पेपर 10 लाख रुपये में खरीदा और हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख रुपये में बेचकर 5 लाख रुपये का मुनाफा कमाया। रिपोर्टों के अनुसार, पेपर एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए प्रसारित किया गया।

2 मई की रात 11 बजे, राजस्थान

## मुलायम के छोटे पुत्र का निधन

-जाल खंबाता-  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-  
नई दिल्ली, 13 मई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का लखनऊ में 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें बुधवार को लखनऊ सिविल अस्पताल

■ स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव (38 वर्ष) लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे।

मृत अवस्था में लाया गया।

वे भाजपा नेता अर्पणा यादव के पति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्हें सुबह 6:15 बजे उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी उस समय मौजूद नहीं थीं।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम जल्द ही उनके शरीर का पोस्टमॉर्टम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बाबूलाल कटारा की पुलिस रिमांड 16 मई तक बढ़ी

जयपुर, 13 मई। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने कृषि विज्ञान प्राध्यापक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने सह आरोपी और कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को 27 मई तक जेल भेज

■ एसीबी कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में संजय बडाय्या को जेल भेजा।

दिया है। वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी संजय बडाय्या को 19 मई तक जेल भेज दिया है।

रिमांड अवधि पूरी होने पर एसओजी की ओर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। एसओजी की ओर से कहा गया कि आरोपी से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ट्रंप व शी की मुलाकात, दो एकदम फर्क सोच व शासन के बीच मुकाबला है?

### ट्रंप की स्टाइल, नाटकीय सौदेबाजी, सार्वजनिक धमकियां, अचानक बातचीत सफल होने की घोषणा पर निर्भर करती है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। डॉनल्ड ट्रंप 13 से 15 मई के बीच शी जिनपिंग के साथ वार्ता करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर संभवतः अमेरिका और चीन के बीच नहीं, बल्कि नेतृत्व, निर्णय लेने की शैली और रणनीतिक समय सीमा के दो मौलिक रूपों के बीच हो सकता है।

ट्रंप थू-राजनीति को सामरिक दृष्टि से लेन-देन के आधार पर आधारित और प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से देखते हैं। उनकी कूटनीति शिखर वार्ता-केन्द्रित और मीडिया-केन्द्रित है, जो तत्काल दृश्यता और सबसे छोटे मीडिया लाभ पर भी काफी ध्यान देती

है। वे जल्दी ही ऐसे परिणाम चाहते हैं, जो दिखाई दें। टैरिफ, नाटकीय वार्ता, सार्वजनिक धमकी, और तेजी से सफलता की घोषणाएँ आदि उनके तरीके हैं। सफलता राजनीतिक रूप से और तुरंत मापी जाती है।

इस शैली की अपनी ताकत है। ट्रंप सहज रूप से एक्सेलेशन (उत्काने) के मनोविज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि अप्रत्याशितता स्वयं वार्ता का एक जरिया बन सकती है। वे यह भी समझते हैं कि पारंपरिक विदेश नीति की नौकरशाही अक्सर स्थिर, धीमी और धरेलू राजनीतिक भावना से अलग हो जाती है।

लेकिन सामरिक नेतृत्व अस्थिरता भी पैदा करता है।

■ दूसरी ओर शी की स्टाइल में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत बजाय संस्थागत होने के। औपचारिक सलाहकार संरचनाएँ कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि प्रभाव अनौपचारिक नेटवर्क, व्यक्तिगत मित्रावादी, मीडिया की कहानियाँ, व्यावसायिक आंकड़ों

ट्रंप के शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत बजाय संस्थागत होने के। औपचारिक सलाहकार संरचनाएँ कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि प्रभाव अनौपचारिक नेटवर्क, व्यक्तिगत मित्रावादी, मीडिया की कहानियाँ, व्यावसायिक आंकड़ों

और संपर्क के तदर्थ चैनलों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। नीति अक्सर अनुशासित अंतर-एजेंसी प्रक्रिया के बजाय, सहज ज्ञान, बातचीत और राजनीतिक आवेग से प्रेरित होती है। यह न केवल विरोधियों के लिए, बल्कि मित्र और अमेरिकी संस्थानों के लिए भी अस्थिरता पैदा करता है। संकेत तेजी से बदलते हैं। स्थिति अचानक कभी मुश्किल तो कभी नरम हो जाती है। अधिकारी एक हफ्ते में सशक्त होते हैं और अगले हफ्ते हाशिए पर चले जाते हैं। नीति की दिशा ट्रंप के अपने राजनीतिक आवेग, व्यक्तिगत अटपटे

रवैये और प्रतिक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है।

शी की नेतृत्व शैली अत्यधिक केन्द्रीकृत है, लेकिन क्रियान्वयन में गहराई से संस्थागत है। निर्णय पार्टी संरचनाओं, आंतरिक समितियों, औपचारिक पदानुक्रम और अनुशासित नौकरशाही श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। शी तात्कालिक फैसलों की बजाय केन्द्रीकृत तरीके से शासन करते हैं।

शी की प्रणाली में भी अपनी कमजोरियाँ हैं, विशेष रूप से अत्यधिक केन्द्रीकरण और पीएलए नेतृत्व के भीतर बढ़ती अशांति। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत चीनी राज्य की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## विजय ने विश्वासमत जीता, अन्नाद्रमुक के 27 विधायकों ने समर्थन दिया

चेन्नई, 13 मई। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगना वेत्रि कडगम (टीवीके) सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विजय को अपना बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता

■ टीवीके सरकार को बहुमत साबित करने के लिये 118 मतों की आवश्यकता थी, पर उसे 144 मत प्राप्त हुए।

थी, लेकिन उन्हें सदन में 144 विधानसभा सदस्यों का समर्थन मिला। सरकार के पक्ष में एआईएडीएम के 27 सदस्यों ने भी मतदान किया।

सुबह 9:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू की। इसके बाद टीवीके की सरकार के विश्वास मत के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



# 'गर्मी के मौसम में आमजन को नहीं हो कोई परेशानी'

## मुख्यमंत्री ने पानी-बिजली आपूर्ति को लेकर दिए सख्त निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर एवं विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी तय होगी।

- शिकायतों की हो नियमित मॉनिटरिंग, असुविधा होने पर जिला कलक्टर की जिम्मेदारी होगी तय
- 'आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता'
- किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी जिला कलक्टर नियमित रूप से पानी-बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर निरंतर मॉनिटरिंग करें। संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ त्वरित

इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के अनुरूप पेट्रोल-डीजल बचत के लिए सभी अधिकारी भी वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतें। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहनों का न्यूनतम उपयोग करें तथा अधिकाधिक कार पब्लिक व्यवस्था अपनाएं। साथ ही, जिलों में वीसी के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिला कलक्टर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।

इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## ऑनलाइन कंपनी के पार्सल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश

जयपुर। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पार्सलों की दिनदहाड़े लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 1135 पार्सल और वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बरामद माल की कीमत करीब चार लाख रुपए आंकी गई है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 7 मई 2026 को परिवारवादी दिल्ली पार्सल ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह कंपनी के पार्सल लेकर मद्रासपुर स्थित वेयरहाउस जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार अनिल चौधरी और उसके साथियों ने रास्ते में उसे रोक लिया।

आरोपियों ने दिल्ली का अपहरण कर उसे रिंग रोड स्थित सीतापुरम टोल प्लाजा के पास ले गए और वाहन में रखे 1386 पार्सल, मोबाइल फोन और गाड़ी की बैटरी लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर

शर्मा और एसपी चक्रवर्ती सिंघ के निर्देशन में थानाधिकारी अनिल जैमनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में अनिल चौधरी (24) निवासी देवपुरा, फागी और रामप्रसाद जाट (31) निवासी देवपुरा, फागी शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी अनिल चौधरी पहले इसी ऑनलाइन कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम करता था। उसे कंपनी के रूट और कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी थी।

पुलिस के अनुसार अनिल को लज्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन कम सैलरी के कारण उसके खर्च पूरे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से उसने साथी रामप्रसाद और फरार आरोपी रोहित देवन्दा को मोटी कमाई का लालच देकर लूट की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों से कुर्तियां और बेडशीट सहित 1135 पार्सल बरामद कर लिए हैं।

## अपरा एकादशी मनाई

जयपुर। सुभाष चौक पानो का दरवा स्थित श्री शुक सम्प्रदाय आचार्य पीठ सरस निकुंज के में आयोजित अष्टयाम सेवा महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को अपरा एकादशी पर रास महोत्सव

संपन्न हुआ। श्री शुक सम्प्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सान्निध्य में टाकुर श्री राधा सरस विहारी जू सरकार के दिव्य दर्शन कराए गए।

## आईटीएटी रिश्वत प्रकरण में न्यायिक सदस्य को जमानत से इनकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अपील न्यायिक अधिकरण में रिश्वत से जुड़े मामले में न्यायिक सदस्य रही एस. सीतालक्ष्मी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर उसे जमानत देना उचित नहीं है।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने अधिकरण में न्यायिक सदस्य पद पर रहते हुए मैसर्स गोकुल कृपा

कॉलोनाइजर्स तथा डेवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में निर्णय पारित कर लगभग 90 करोड़ रुपये की पेनल्टी माफ कर दी। वहीं रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए खुद ने लिए, जो उसके निवास पर सरकारी वाहन से बरामद हुए। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि उसके घर की तलाशी में एक नेकलेस व एक आईफोन भी बरामद हुआ और इन्हें भी उसने रिश्वत के तौर पर लिया था।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में गत 22 जनवरी को आरोप पत्र पेश होने के बाद अभियोजन स्वीकृत जारी नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को धारा 19 के

## 'जेडीए उच्चतम बोलीदाता को सौंपे भूमि का कब्जा'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट के पास स्थित भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा. लि. को नई डिमांड जारी करे और शेष राशि जमा होने पर भूमि का कब्जा उसे सौंपे।

## खाद्य सुरक्षा विभाग की दूध केंद्रों पर छापेमारी

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को जयपुर द्वितीय क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध संकलन केंद्रों और बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों

के दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। कार्रवाई आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया

कि विभाग को मिले विशेष निर्देशों के बाद गठित टीमों ने दूध, बगरू और दही कलां क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दूध संकलनकर्ता फर्मों और बीएमसी केंद्रों की गहन जांच की गई। जांच दल को संदिग्ध प्रतीत होने वाले दूध के नमूने एकत्रित कर खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

**RIICO**

**RAJASTHAN**

### जयपुर की प्राइम लोकेशन

**टॉक रोड तथा बी 2 बाईपास जंक्शन के पास प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम के नजदीक होटल भूखण्डों का आवंटन**

सरल ई-नीलामी के माध्यम से

जयपुर में विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल विकसित करने हेतु सुनहरा अवसर

<b>ईएमडी</b>	<b>आरम्भ तिथि: 14 मई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे)</b>	<b>ऑनलाइन बidding</b>
	<b>अंतिम तिथि: 28 मई, 2026 (सायं 06:00 बजे)</b>	<b>आरम्भ तिथि: 29 मई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे)</b>
		<b>अंतिम तिथि: 01 जून, 2026 (सायं 05:00 बजे)</b>

**भूखण्ड विवरण**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूखण्ड संख्या - H-1</li> <li>• क्षेत्रफल - 28,250 वर्ग मीटर</li> <li>• आवंटित दद - ₹1,50,000 प्रति वर्गमीटर</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूखण्ड संख्या - H-2</li> <li>• क्षेत्रफल - 20,025 वर्ग मीटर</li> <li>• आवंटित दद - ₹1,50,000 प्रति वर्गमीटर</li> </ul>
---	---

**बिल्डिंग पैरामीटर्स**

**Maximum Ground Coverage: 35% || B.A.R. (Standard): 2.0**

**Maximum Height of Building: 1.50 Times of Road Width + Front Setback**

**भुगतान संबंधी शर्तें**

25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 3 त्रैमासिक किस्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

भूखण्ड की कुल प्रीमियम राशि पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा

**राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

उद्योग भवन, विलक मार्ग, सी-स्कैन, जयपुर 302005

जयपुर (दक्षिण) इकाई कार्यालय- वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक- 9414061911 ईमेल/फोन नं. 0141-4593250, 4593237, कार्सफॉन +91 9001306515, आदतन से संबंधित त्रिवर्गीय एवं शर्तों, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से संबंधित जानकारी हेतु रीको के इकाई कार्यालय जयपुर (दक्षिण), मालवीय नगर में संपर्क करें या देखें <https://riico.rajasthan.gov.in>

# MGH है, तो भरोसा है

## सम्पूर्ण उपचार सेवाएं एक ही स्थान पर

सुपर स्पेशियलिटी जनरल स्पेशियलिटीज कंप्यूटराइज्ड जांच सेवाएं आपातकालीन सेवाएं

**कैंसर चिकित्सा**

- कीमोथेरेपी • रेडियो थेरेपी • बोनमैरो ट्रांसप्लांट
- सभी प्रकार के कैंसर ऑपरेशन, जांच व उपचार

**लिवर ट्रांसप्लांट**

बच्चों एवं वयस्कों के पेट, लिवर, आंत रोगों का मेडिकल व सर्जिकल उपचार

**किडनी प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग, यूरोलॉजी**

• बच्चों व वयस्कों के किडनी व पेशाब सम्बंधी उपचार

**हृदय रोग, EP & RFA हृदय शल्य चिकित्सा**

शिशु एवं वयस्कों के सभी प्रकार के हृदय रोगों की जांच व उपचार सेवाएं

**न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी न्यूरोइंटरवेंशन उपचार**

**जोड़ प्रत्यारोपण स्पोर्ट्स इंजरी**

बोन कैंसर उपचार एवं ट्रॉमा सेवाएं

**निसंतानता, स्त्री एवं प्रसूति रोग**

- IVF उपचार सेवाएं • स्त्री रोगों के रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन

**शिशु एवं बाल रोग की सम्पूर्ण सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं**

- शिशु आपातकालीन सेवाएं • शिशु श्वास रोग • बाल गहन चिकित्सा • नवजात रोग • शिशु हृदय रोग, हृदय शल्य चिकित्सा
- शिशु पेट, लिवर रोग एवं लिवर ट्रांसप्लांट • शिशु शल्य चिकित्सा • शिशु गुर्दा रोग - डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट
- शिशु न्यूरोलॉजी एवं एपिलेप्सी • शिशु हार्मोन रोग व डायबिटीज • शिशु रक्त एवं कैंसर रोग व बोन मैरो ट्रांसप्लांट • अनुवांशिक रोग

इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ - बच्चों के (0 से 18 वर्ष) शारीरिक, मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य सेवाएं **NICU, PICU**

**सायबरनाइफ S7**

2800+ किडनी ट्रांसप्लांट्स | 172+ लिवर ट्रांसप्लांट्स | 250+ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स

1450 बैड्स | 550+ डॉक्टर्स | 1000+ नर्सिंगकर्मी | 350+ ICU एवं क्रिटिकल केयर बैड्स

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) | राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS)

योजना के लाभार्थियों के लिए ECHS, CGHS, All Major Mediclaim Cos. & TPAs से उपचार हेतु अधिकृत

रोबोटिक सर्जरी

जटिल रोगों के ऑपरेशन की अत्याधुनिक तकनीक

**महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर**

**श्री राम कैंसर एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेन्टर**

(A UNIT OF MAHATMA GANDHI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, JAIPUR.)

A Multi Super Speciality Teaching Hospital of the University (NAAC A+, NABH, NABL, NABH - Blood Bank) Accredited

रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टॉक रोड, जयपुर - 302022 फोन : 0141-2771777, 2771001-2-3 Website : www.mgumst.org टोल फ्री नं. 18001806002 हैल्पलाइन नं. 8107677888



**सूरतगढ़ विद्युतगृह की इकाईयों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन**

जयपुर। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की 2 सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग एवं उत्पादन निगम के प्रबन्धन को बधाई देते हुए बताया कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की सुपरक्रिटिकल तकनीक पर आधारित 2660 मेगावाट क्षमता की इकाई 7 एवं 8 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिक अवधि में इन इकाईयों में कुछ तकनीकी खामिया थीं, जिन्हें लगातार प्रयास कर सफलतापूर्वक दूर किया गया। दोनों सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने उत्पादन निगम के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग एवं उत्पादन निगम के प्रबन्धन को बधाई देते हुए बताया कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने उत्पादन निगम के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग एवं उत्पादन निगम के प्रबन्धन को बधाई देते हुए बताया कि सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की सुपरक्रिटिकल इकाईयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने उत्पादन निगम के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

**जल जीवन मिशन घोटाले में संजय बड़ाया को जेल भेजा**

जयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले की जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बुधवार को पूर्व पीएचडी मंत्री डॉ. महेश जोशी के करीबी माने जाने वाले संजय बड़ाया को अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। संजय बड़ाया पर पीएचडी अधिकारियों और ठेकेदारों से मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी करवाने तथा ड्राइंग-पोस्टिंग के नाम पर रिश्वतखोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं।

एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि संजय बड़ाया को 11 मई को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उसे जयपुर लाकर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा था। रिमांड अवधि समाप्त होने पर बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेजने के आदेश दिए।

जांच में सामने आया है कि श्रीगणपति टचयूवेल कंपनी के

**पाटोत्सव आयोजित**

जयपुर। चांदपोल बाजार के नींदड़ राव जी का रास्ता स्थित मंदिर श्री नृसिंह जी अग्रवाल पंचायत समिति के तीन दिवसीय पाटोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को बराह लीला के दर्शन कराए गए। चांदपोल बाजार में बराह भगवान की झांकी को देखने श्रद्धालु निर्धारित समय से पहले ही बरामर्दी में खड़ हो गए। मुख्य झांकी से पहले श्री हनुमान जी की जीवंत झांकी निकाली गई। नींदड़ राव जी का रास्ता स्थित श्री नृसिंह जी मंदिर में महंत पं. मनमोहन शर्मा के सांनिध्य में समाजसेवी चंद्र मोहन बटवाड़ा, मंदिर श्री नृसिंह अग्रवाल पंचायत समिति के अध्यक्ष चेतन अग्रवाल, मंत्री कैलाश चंद्र अग्रवाल एवं अन्य ने महाआरती कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। जैसे ही जल से बराह भगवान प्रकट हुए तो मंदिर परिसर जयकारों से गुंज उठा।

उल्लेखनीय है कि भगवान विष्णु का वराह अवतार उनके दस प्रमुख अवतारों (इशावतार) में तीसरा है, जिसमें उन्होंने सत्य युग में एक विशाल सूअर का रूप धारण किया था।

**कल्चरल इंटेलिजेंस और सोल डेवलपमेंट को अपनाएं : वासुदेव देवनानी**



राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वीएसएचएफ के महाधिवेशन एवं यूथ सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए।

नवाचार, स्वरोजगार और डिजिटल स्किल्स पर फोकस होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही युवाओं को सोल डेवलपमेंट: चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक सोच पर बल देना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि ज्ञान और संस्कार का त्रिवेणी संयोग ही विकसित भारत 2047 का मजबूत

- वीएसएचएफ का मुंबई में प्रथम महाधिवेशन एवं यूथ सम्मेलन हुआ
- देवनानी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधी समाज की एकता पर विशेष जोर दिया

मूल्य दोनों हैं। देवनानी ने युवाओं से कहा कि मशीनों के काम कर लेंगे, लेकिन दिल और आत्मा का विकास मानव को विशिष्ट बनाएगा। देवनानी ने युवाओं से अपील की कि वे जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाएं। वासुदेव देवनानी ने युवाओं से अपील की कि वे जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाएं। वासुदेव देवनानी ने युवाओं से अपील की कि वे जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम की भावना अपनाएं।

नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और वैश्विक चुनौतियों (जैसे अप्रीका के संदर्भ में) का सामना करने के लिए तैयार

रहें। उन्होंने युवाओं की नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी और पॉलिटेक्स में सकारात्मक भूमिका और पार्टिशन की मानसिकता से मुक्ति पर विशेष चर्चा की। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा में युवा संसद, युवा संवाद और विकसित भारत युवा संसद जैसे कार्यक्रमों के प्रमुख संदेश देते हुए कहा कि सिंधी युवा भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज का युवा देश की प्रगति, अखंडता और सामाजिक सद्भाव का आधार स्तंभ है। वे अपने ज्ञान, कौशल, समर्पण और राष्ट्रप्रेम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी विजन और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (आयुष्मान भारत, स्टार्टअप इंडिया, शिक्षा, रोजगार) की प्रशंसा की।

**लिव-इन पार्टनर का गला दबाकर कत्ल**

जयपुर। राजधानी के मुरलीपुरा थाना इलाके में महिला की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसके लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर अन्य लोगों से बातचीत को लेकर हुए विवाद में महिला का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी एक महिला मित्र की हत्या के मामले में जेल जा चुका है।

मृतका की पहचान टॉक जिविले के वनेटा निवासी 25 वर्षीय अंबिका कुमारी बैरागी के रूप में हुई है। हत्या के आरोपी में पुलिस ने चितानी निवासी रामकल्याण गुर्जर को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले करीब तीन महीने से जयपुर के मुरलीपुरा स्थित जीवनदीप कॉलोनी में किए गए के मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

डॉसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 9 मई को पुलिस को जीवनदीप कॉलोनी के एक मकान में महिला का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को मकान मालिक ने बताया कि महिला के साथ रहने वाला युवक घटना के बाद से गायब है।

**राजस्थान यूनिवर्सिटी में खुलेगा सरस पार्लर**



आरसीडीएफ की श्रुति भारद्वाज व कुलपति प्रो. अल्पना, रजिस्ट्रार आशु चौधरी, मंजू चौधरी व जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार की उपस्थिति में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।

यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रार आशु चौधरी एवं जयपुर डेयरी की ओर से प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों के तहत जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों को प्रमुख मंदिरों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक

उपयोगिता स्थलों पर सरस पार्लर एवं सरस स्मार्ट बूथ स्थापित करने हेतु उल्लेख्य कराने से भूमि एवं स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी अभियान के अंतर्गत राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में सरस पार्लर प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों एवं आमजन को गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद सुलभ हो सकेंगे।

**बड़ाया पर ठेकेदारों से मिलीभगत कर टेंडर प्रक्रिया में ड्राइंग-पोस्टिंग के नाम पर रिश्वतखोरी में शामिल होने के गंभीर आरोप हैं**

प्रोपराइटर महेश मित्तल और श्रीरथाम टचयूवेल कंपनी के प्रोपराइटर प्रदमचंद्र जैन ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण-पत्र तैयार कर जल जीवन मिशन के तहत करीब 960 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए। एसीबी जांच में इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन मंत्री डॉ. महेश जोशी, विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, कई मुख्य अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों, ठेकेदारों और संजय बड़ाया की मिलीभगत सामने आई है। एसीबी के अनुसार 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि के टेंडरों में साइट विजिट प्रमाण-पत्र की शर्त जोड़ने में भी संजय बड़ाया की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

**युवाओं के भविष्य की सुरक्षा भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मदन राठौड़**

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रकरण में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई करते हुए परीक्षा रद्द कर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा की नीति प्रघ्न्याचार और पेपर लीक जैसे अपराधों के खिलाफ जोरो टॉलरेंस की है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली या निकट का व्यक्ति क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। राठौड़ ने कहा कि गलतों साहब को गलत जानकारी है, बिना तथ्यों के भाजपा पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को लेकर ये बात कर रहे हैं, वो

**पेपर लीक मामले में दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई, भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति : मदन राठौड़**

हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आजकल सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवा लेना सामान्य बात है, लेकिन केवल फोटो के आधार पर किसी को पार्टी से जोड़ना उचित नहीं है। यहां स्पष्ट कर दूं कि हम किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेपर लीक का मामला केरल से शुरू हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न राज्यों तक पहुंचा। राजस्थान का इस पूरे प्रकरण में प्रत्यक्ष

संबंध सामने नहीं आया है। उन्होंने केंद्र सरकार और एनटीए की सराहना करते हुए कहा कि परीक्षा परिणाम आने से पहले ही परीक्षा रद्द कर नई परीक्षा आयोजित करने का निर्णय विद्यार्थियों के हित में बड़ा और साहसिक कदम है। राठौड़ ने कहा कि विद्यार्थियों को दोबारा आवेदन या शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा तथा पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे छात्रों को न्याय मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पेपर लीक का मामला केरल से शुरू हुआ और सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न राज्यों तक पहुंचा। राजस्थान का इस पूरे प्रकरण में प्रत्यक्ष

**‘देश समृद्ध की भावना के साथ कार्य कर रही है सरकार’**

जयपुर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है।

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों की में बढ़ोतरी करना किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शी फैसला है। इससे देश के करोड़ों किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र को मजबूती प्राप्त होगी।

सीपी जोशी ने कहा कि धान की में 72 रुपये की वृद्धि कर 2441 रुपये प्रति क्विंटल तथा तुअर/अरहर की में 450 रुपये की वृद्धि करना किसानों के प्रति केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को

दशांता है। वहीं मूंगफली, कपास, तिल, सूरजमुखी, उड़द, बाजरा सहित अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी किसानों के लिए राहत देने वाली है।

सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अग्रदाता सुखी तो देश समृद्ध की भावना के साथ कार्य कर रही है। व्यवस्था किसानों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है और यह किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।

सीपी जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में लगातार ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है। यह निर्णय किसानों की मेहनत का सम्मान करने वाला तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित होगा।

**सार-समाचार**



जयपुर। अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर में पुरातन छात्र समिति द्वारा पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मॉन सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध समाजसेवी इन्द्रचन्द्र गुप्ता-सेवानिवृत्त जिला प्रबन्धक यूको बैंक एवं विशिष्ट अतिथि डॉ. अख्तर रिजवी-सहायक निदेशक अल्पसंख्यक मामलात, राजस्थान सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केशव विद्यापीठ समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता ने की। इस कार्यक्रम में केशव विद्यापीठ समिति सचिव मेघसिंह चैहान, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार अग्रवाल ने की। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. रीता शर्मा, उप प्राचार्य डॉ. सतीश चन्द मंगल, पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष डॉ. बी.के. गुप्ता, सचिव प्रो. मुदित राठौड़ एवं कोषाध्यक्ष डॉ. रेवत सिंह मंचासीन रहे।

**गुरुदेव रविशंकर के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित**

जयपुर। गुरुदेव रवि शंकर के 70वें जन्मोत्सव एवं आर्ट ऑफ लिविंग के 45 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बुधवार को प्रताप नगर स्थित रवि शंकर आश्रम में सेवा, साधना एवं सत्संग के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः आयुष होम (हवन) से हुई, जिसमें विश्व शांति एवं जनकल्याण की प्रार्थना की गई। सायंकाल आयोजित सामूहिक सुदर्शन क्रिया में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा सिखाई जाने वाली सुदर्शन क्रिया विश्व के 190 देशों में प्रचलित श्वास तकनीक है, जो तनाव निवारण एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। शाम 5 बजे से आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। इसके पश्चात आयोजित भव्य सत्संग में भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आर्ट ऑफ लिविंग की अनसंग हीरोज मुहिम के अंतर्गत जयपुर से चयनित सेवावीरों को सम्मानित किया गया। जयपुर जिले से यह सम्मान "घूंघट प्रथा मुक्त ग्राम अभियान तथा जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूकता" के लिये 85 वर्षीय डॉ मालती गुप्ता एवं "राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता और जमीनी स्तर के अगली पीढ़ी के नेतृत्व संवर्धन" के लिये 33 वर्षीय शुभम शर्मा को प्रदान किया गया।

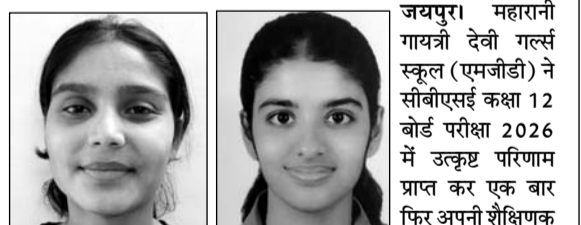
**परशुराम ज्ञानपीठ में 20 मई से शुरू होगा पहला बैच**

जयपुर। विप्र फाउंडेशन द्वारा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं को बेहतर तैयारी प्रदान करने के उद्देश्य से शिप्रा पत्र, मानसरोवर स्थित परशुराम ज्ञानपीठ में 20 मई से एएसएससी कोचिंग प्रारंभ की जाएगी। परशुराम ज्ञानपीठ संवाहन समिति के सचिव सतीश शर्मा ने बताया कि आठ से दस माह अवधि के इस कोर्स की कोचिंग अत्यंत सामान्य शुल्क पर उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि कोचिंग के दौरान प्रत्येक माह टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। टेस्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रथम तीन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित हो सके। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस एन श्रीमाली ने बताया कि वर्तमान में ज्ञानपीठ में आरएएस/आईएएस कोचिंग, लाइब्रेरी, कन्या छात्रावास एवं अतिथि कक्ष जैसी सुविधाएं संचालित हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 बैच के 113 आरएएस अभ्यर्थियों को मांक इंटरव्यू की तैयारी करवाई गई थी, जिनमें से 54 अभ्यर्थियों का आरएएस में चयन हुआ। उन्होंने विश्वास जताया कि एएसएससी कोचिंग शुरू होने से प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन और शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा।

**जयपुर पुलिस कमिश्नर 17 को पुलिस थाना रामगंज पर करेंगे जनसुनवाई**

जयपुर। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल 17 मई (रविवार) को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक पुलिस थाना रामगंज पर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान रामगंज सर्किल के रामगंज, गलता रोड एवं माणक चौक सर्किल के माणक चौक, सुभाष चौक, महिला थाना उत्तर थानों के परिवारियों की जनसुनवाई की जाएगी। इस जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवारियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है। गौरतलब है कि इससे पूर्व पुलिस कमिश्नर द्वारा एसीपी कार्यालय झोटावाड़ा, सामुदायिक भवन सांगानेर, पुलिस थाना शिप्रानगर, विद्याधर नगर, भांकरोटा, शिवदासपुरा, आमेर एवं बस्सी में जनसुनवाई कर परिवारियों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा चुका है।

**एमजीडी गर्ल्स स्कूल का सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन**



जयपुर। महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल (एमजीडी) ने सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर एक बार फिर अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता सिद्ध की है। विद्यालय की छात्राओं ने तीनों संकायों में शानदार प्रदर्शन किया। ह्यूमैनिटीज संकाय की छात्रा आनेया जैन ने 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। कॉमर्स संकाय में नंदिता जैन ने 97.8 प्रतिशत तथा सौम्या गठानी ने 97.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। विज्ञान संकाय में जाह्नवी सिंह ने 95.4 प्रतिशत अंक अर्जित किए। विद्यालय का कुल औसत परिणाम 85.24 प्रतिशत रहा। इसी परीक्षा में विद्यालय की छात्रा सानवी टाक ने अदय्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। वर्ष 2025 में उनकी स्थिति गंभीर होने पर उन्हें सप्ताह में तीन बार डायलिसिस कराना पड़ा। तथा जयपुर के एमजीडी गर्ल्स स्कूल को छात्रा आशि उपाध्याय ने 12 कक्षा (साइंस बोर्ड) में 95 प्रतिशत अंक हासिल किया। आशी ने इसी वर्ष बैंगलुरु में आयोजित 2 (स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया) की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। आशी अन्तर्राष्ट्रीय वरीयता प्राप्त शतरंज खिलाड़ी है।

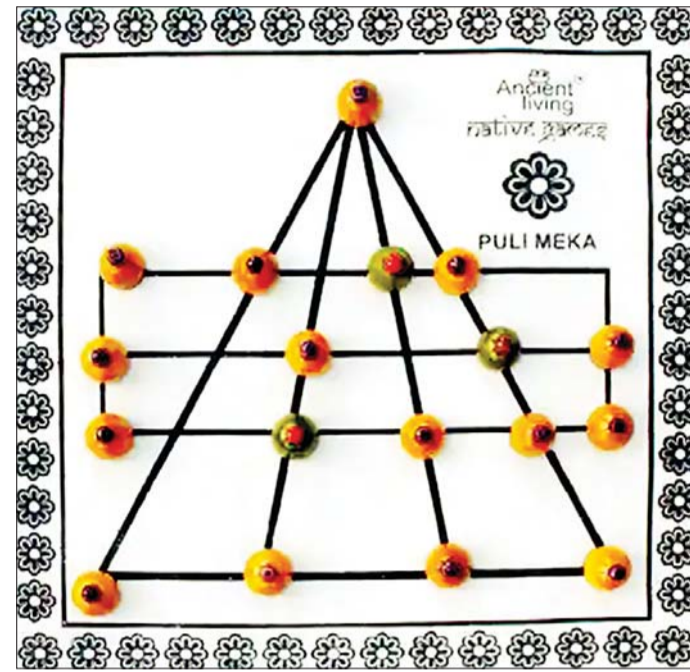
**रक्तदान कर बम ब्लास्ट के शहीदों को श्रद्धांजलि दी**

जयपुर। सन् 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में शहीद हुए नागरिकों की स्मृति में बुधवार को अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। छोटी चौड़ पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। बम कांड में मारे गए लोगों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सांगानेरी गेट पूर्य मुखी हनुमान मंदिर, चांदपोल हनुमान मंदिर में भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भक्ति में कभी भी इस तरह की आतंकीय घटना न हो ऐसी प्रार्थना की। सर्व समाज रक्तदाता संस्था के तत्वावधान में रक्तदान शिविर एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं आमजन ने भाग लेकर बम धमाके में शहीद हुए लोगों को श्रद्धासमन अर्पित किए। सांसद मंजू शर्मा, हवामहल विधायक बालमुकुंददाचार्य, भाजपा नेता चन्द्र मनोहर बटवाड़ा, सर्व समाज रक्तदाता संस्था की प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा शर्मा ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया।

## #AADU PULI ATTAM

### The Game on the Temple Steps

The tigers are powerful. The goats are weak individually. But have strength in numbers. If they collaborate, surrounding the tigers and blocking, they win



Not too far from Anantya, tucked quietly inside a village temple courtyard, there is a stone step worn smooth by time, bare feet, monsoon rain, and generations of conversation. At first glance, it looks ordinary. But if you look closely, etched into the surface is a game board, simple lines intersecting into triangles and pathways. Villagers know it well. It is the board for Aadu Puli Attam, the ancient game of goats and tigers.

In the afternoons, after work in the fields, farmers and local elders gather around it. No glossy packaging. No digital screen. Just pebbles, seeds, or bottle caps standing in for the pieces: three tigers and twelve goats.

The rules are deceptively simple. The tigers are powerful. They can leap and capture. The goats are weak individually. One goat alone is easy prey. But the goats have strength in numbers. If they collaborate carefully, surrounding the tigers and blocking every move, they win.

And that is where the game becomes more than a game. India's most celebrated royal strategy game was chess, the game of kings and queens. In chess, every piece exists to protect the crown. Pawns are sacrificed. Knights fall. Bishops disappear. The logic is hierarchical survival of the ruler matters most. Anyone can be compromised for the glory of the king.

But Aadu Puli Attam carries a very different philosophy.

Here, the weak survive not through dominance, but through cooperation. Every goat matters. Even the smallest move affects the whole community. If one goat breaks formation, the tigers gain power. If the goats remain united, even the strongest predator becomes helpless.

The lesson feels deeply rooted in village life itself. In a village, happiness rarely comes from individual success alone. Crops are harvested together. Wells are shared. Festivals belong to everyone. Even the watchman of the village matters because



### Shashank Agarwal Advocate High Court of Rajasthan

My neighbour's son, a bright, cheerful boy who cleared his Class XII boards with distinction, spent six months glued to a phone, playing online card games for money. By the time his family found out, he had quietly emptied a fixed deposit his grandfather had opened in his name. He is not alone. Somewhere in Ajmer, a retired schoolteacher lost most of her pension to an app that promised "double your money in minutes." In Kota, a student preparing for engineering entrance exams found himself borrowing from friends to fund his "next winning streak." These are not imagined situations. They were played out in thousands of homes across Rajasthan and the rest of India, quietly before anyone in authority paid serious attention.

Think about the last time you watched an IPL match. Somewhere between the sixes and the wickets, an advertisement popped up, a celebrity grinning at the camera, telling you that depositing a hundred rupees on some gaming app could make you rich by morning. You probably ignored it. But millions of people did not. And that, in a sentence, is how India ended up with one of the most unregulated, most exploitative online gaming markets in the world.

The industry did not grow gradually. It detonated. A leading market player brought data prices crashing down, smartphone prices followed, and suddenly, a farmer in rural Barmer and a college student in Jaipur had equal access to the same betting apps that were plastered across every cricket broadcast, every YouTube video, every billboard outside a coaching institute in Kota. The platforms knew exactly what they were doing. The advertising was designed to make gambling feel like a skill, a sport, an investment. The terms and conditions, buried in small print, told a different story.

Behind this chaos stood a regulatory vacuum that would embarrass a law student. States had their own gambling laws, some ancient, some patchy, almost none written with a smartphone in mind. One State banned fantasy sports; the next State offered quietly allowed it. Companies incorporated themselves in offshore jurisdictions and served Indian users without any Indian authority being able to touch them. When cases came to court, judges in Madras said one thing, judges in Karnataka said another, and nobody quite agreed on what the law and what was not. The platforms watched all this with quiet satisfaction and kept running.

I have been practising law long enough to know that Parliament does not move quickly unless it has to. By 2025, it had to. The Promotion and Regulation of Online Gaming Act was passed in August that year, and the Rules that give it opera-

tional life came into force on 1st May 2026. What follows is my attempt to explain, without the jargon that makes lawyers unpopular at dinner tables, what these laws actually say and what they mean for the ordinary Indian family.

### Three Boxes, One Big Idea

The Act sorts all online games into three categories, and understanding this division is the key to understanding everything else. The first category is e-sports, proper competitive gaming like organised chess championships, DOTA tournaments, or structured mobile gaming competitions, where outcomes depend entirely on the player's skill, strategy, and mental agility, and which are recognised under the National Sports Governance Act, 2025. The second category is online social games, games played for fun, entertainment, or skill-building, with no money on the line. If you spend Sunday evenings solving word puzzles, playing a casual cricket simulation, or racing cars in a free mobile game, this is where you sit. The government wants both of these categories to grow, and the law actively supports them, including by setting up training academies for e-sports and providing government backing for competitive gaming as a legitimate career.

The third category is online money games. This means any game where you put in real money hoping to get more money back. Notice what the law does not ask, it does not ask whether the game requires skill or whether it is pure luck. That question, which Indian courts debated for decades, has been set aside entirely. If real money goes in with the hope of more money coming out, it is an online money game. And it is now banned.

The ban works on three levels. No one can run or host such platforms in India. No one can advertise them, not on television, not on a YouTube pre-roll, not on a cricketer's jersey. And banks, UPI apps, and payment processors cannot handle money going to these platforms. That last point matters enormously. Even if some offshore website keeps running, you cannot legally send money to it from an Indian bank account. The financial

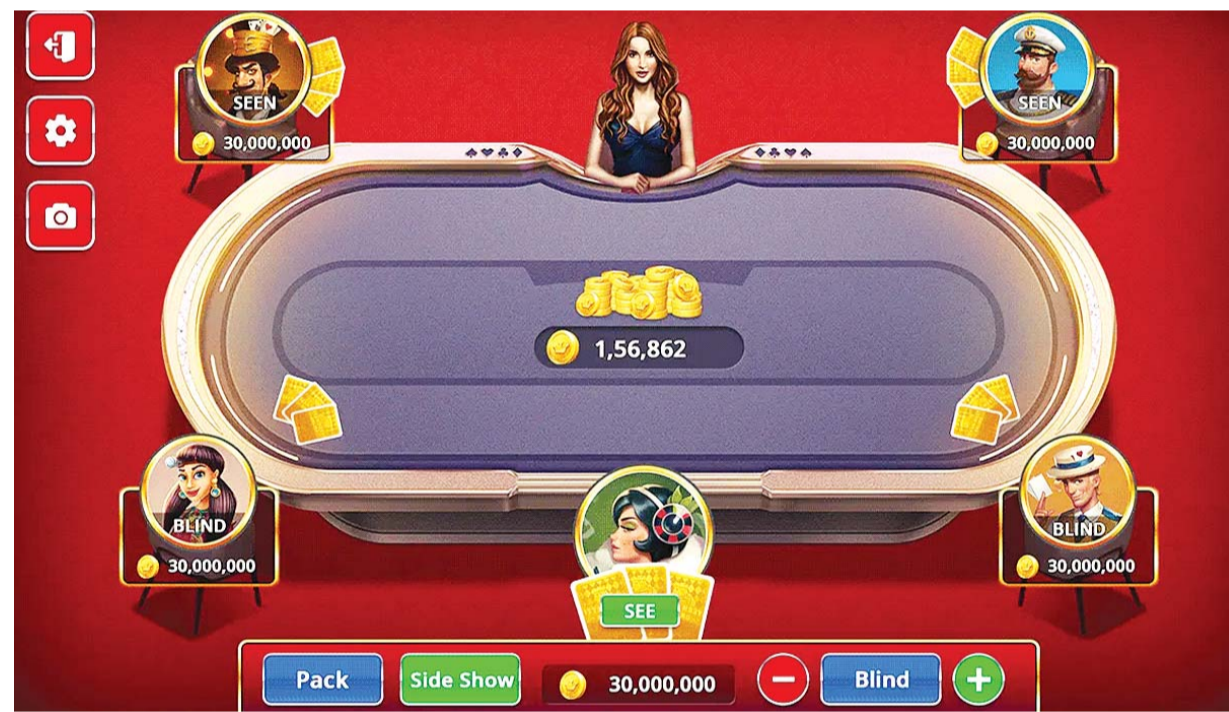
pipeline that kept these platforms alive has been cut.



## Don't Stake Money And You Win!



### #GAMBLING IN YOUR POCKET



### A New Watchdog and What It Will Do

For a law to mean anything, someone has to be responsible for enforcing it. That someone, under the 2026 Rules, is the Online Gaming Authority of India, a new regulatory body sitting under the Ministry of Electronics and Information Technology in Delhi.

Think of it as a referee that the game has been missing for years. The Authority will decide which games fall into the prohibited category of online money games, maintain a publicly accessible list so that users, banks, and advertisers all know exactly which platforms are off-limits, and this is the part that actually matters to most people, hear complaints from users who have been wronged by a gaming company and get nowhere with it. If you raise a grievance with a platform and they brush you off or simply do not respond, you now have

somewhere to go. The Authority can step in, direct the company to act, and if needed, coordinate with banks to choke off the illegal payment flows that keep these platforms running. It can also work directly with law enforcement when criminal prosecution is warranted. That last point is worth sitting with for a moment. Before this law, a user cheated by an online gaming platform had almost no practical recourse. Filing a police complaint about an offshore app felt pointless. Consumer forums moved slowly. The platform simply did not care. The Authority changes that equation, not perfectly, and not overnight, but it changes it. There is now a named, empowered institution whose specific job is to hold these companies accountable.

What I find genuinely worth noting is the user protection rules that every registered gaming platform must now follow. Age verification is mandatory, no minor can create an account. Parents can set time limits and spending controls. Platforms must provide coun-

selling resources and self-exclusion tools for users who recognise they have a problem. These are not suggestions tucked away in a government circular. They are legal requirements backed by real penalties: civil fines up to Rs. 10 lakh, and criminal prosecution leading to three years in prison for first offence and five years for repeat violators. The days of a platform quietly harvesting teenagers' pocket money with no consequences are over, at least on paper.

### Seventy-Five Years of Legal History, Overturned

Here is where things get interesting for those of us who spend our days reading old statutes. In December 1949, the Rajpramukh of Rajasthan promulgated the Rajasthan Public Gambling Ordinance, Ordinance No. 48 of 1949, to punish public gambling and the keeping of common gaming houses. It was a straightforward law for a different era, designed to deal with physical gam-

bling dens in towns and cities. But Section 12 of that Ordinance contained a line that would shape gaming law across India for the next seventy-five years. It said, simply, that the Ordinance would not apply to any game of mere skill, as distinguished from a game of chance, unless it were being run in a common gaming house. That one exemption became the legal scaffolding on which India's entire real-money gaming industry was built. The Supreme Court, in the 1957 case of State of Bombay vs. R.M.D. Chamarbaugwala, held that games where skill dominates over chance are not gambling. Rajasthan courts applied this faithfully. When Dream11 was challenged before the Rajasthan High Court, the judges pointed to Section 12 of the 1949 Ordinance and held that fantasy cricket, requiring statistical knowledge, player analysis, and strategic judgment, qualified as a game of "mere skill" and was therefore outside the reach of gambling law. Fantasy sports companies, rummy platforms, and poker apps all built their legal defence on this doctrine, and for years, it held up. The PROG Act does not engage with this argument at all. It sidesteps it. The new law does not ask whether your game is skill or chance. It asks whether real money is being staked for a monetary return. If yes, it is out.

When Dream11 was challenged before the Rajasthan High Court, the judges pointed to Section 12 of the 1949 Ordinance and held that fantasy cricket, requiring statistical knowledge, player analysis, and strategic judgment, qualified as a game of "mere skill" and was therefore outside the reach of gambling law. Fantasy sports companies, rummy platforms, and poker apps all built

their legal defence on this doctrine, and for years, it held up.

The PROG Act does not engage with this argument at all. It sidesteps it. The new law does not ask whether your game is skill or chance. It asks whether real money is being staked for a monetary return. If yes, it is out. Seventy-five years of carefully developed case law, built on the foundation of a 1949 Ordinance from an undivided Rajasthan, has been legislatively overridden in the online space. Whether that override survives constitutional scrutiny is a separate question, but as the law stands today, the skill exemption no longer protects online money gaming.

### What Happens to Poker?

Let me tell you about a client I met last year, a software engineer from Pune who played online poker seriously, the way some people play chess or follow the stock market. He tracked every hand he played in a spreadsheet. He studied probability tables. He read books on game theory. He was, by an honest measure, genuinely good at the game and made a modest but consistent income from it. When I explained to him what the PROG Act meant for his hobby, he looked at me the way people look at a doctor delivering bad news. "But it's not gambling," he said. "I win because I'm better than the other players." He was not wrong. He was just on the losing side of a legislative decision.

Poker's legal story in India has been a long and genuinely complicated one. The Madras High Court, in 2023, ruled that online poker is a game of skill, deserving the same constitutional protection as any legitimate trade or business. The Karnataka High Court agreed. When a Bengaluru poker club was raided and an FIR filed, the Karnataka High Court quashed it, holding that what the police had witnessed was not gambling but a skill-based game. The Karnataka government appealed all the way to the Supreme Court in 2025. The Supreme Court looked at the matter and refused to interfere with the High Court's order, but in a move that left the entire legal community waiting, it deliberately declined to decide whether poker is skill or chance, leaving the question formally unanswered.

That unresolved question, which courts had been circling for years, became irrelevant almost overnight when the PROG Act came into force. The law does not get into philosophical debates about the nature of poker. It does not care that my client kept spreadsheets or that serious players consistently outperform beginners over thousands of hands. The moment real money is wagered online in expectation of a return, it is an online money game, and it is banned. Adda52, once one of the country's most prominent poker platforms, has shut its real-money operations. The skill argument, valid as it may be intellectually, has no legal home anymore, at least not in the online money gaming space.

What remains legal is worth being clear about. Sitting around a table with friends on a Saturday night and playing poker without money changing hands is perfectly fine. A friendly game of cards will not get anyone arrested. The law is not making a moral judgment about poker as a game. It is making a financial one, wherever real money meets online gaming, the door is now closed.

Several gaming companies, including Head Digital Works, the parent company of the A23 platform, have challenged the Act before the Supreme Court. Their argument is that Parliament has trespassed into state territory, betting and gambling fall under Entry 34 of the State List in the Constitution, and that the blanket ban violates fundamental rights

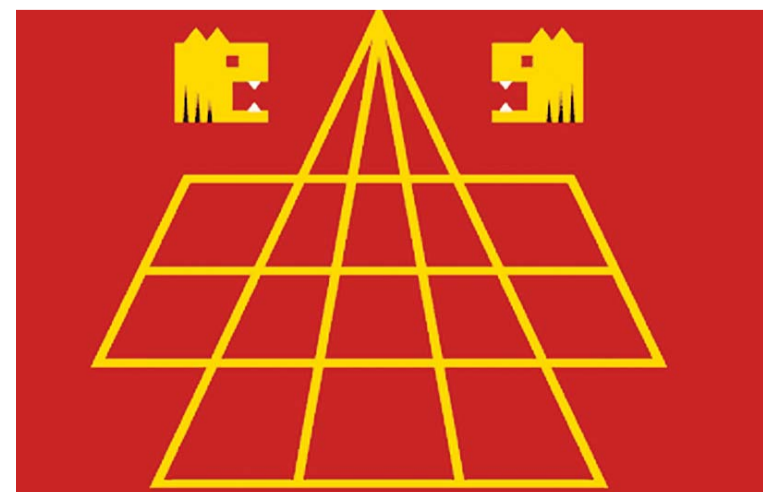
under Articles 14, 19, and 21. All High Court challenges have been consolidated before the Supreme Court and hearings are proceeding. That verdict, whenever it comes, will be among the most significant decisions for India's digital economy.

### Does This Law Actually Help Ordinary People?

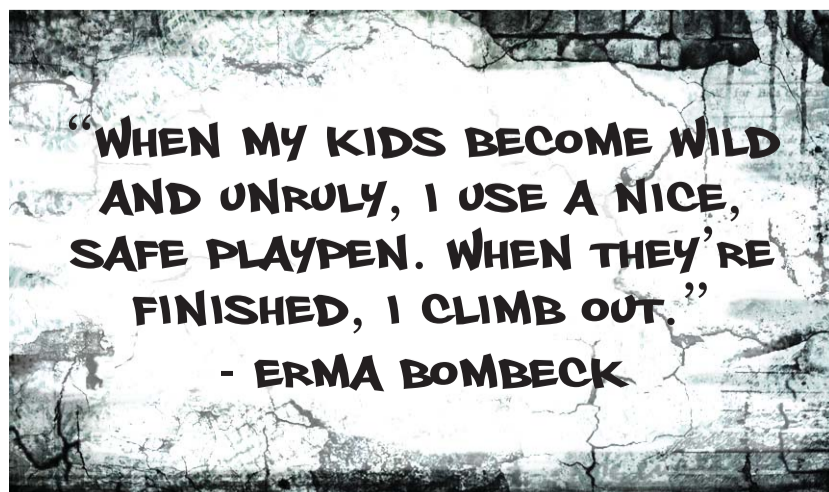
My honest answer is: more than the previous situation did. The neighbour's son I mentioned at the start, under this law, the platform he used would have been prohibited. The bank transfer that funded his spiral would have been blocked at the source. His parents could have set spending and time controls on any registered gaming app he accessed. None of that brings back his grandfather's fixed deposit, but it makes it meaningfully harder for the next teenager to walk the same road.

The law has real shortcomings. Treating a thoughtfully played skill game the same as a manipulative slot machine is a blunt approach. It has put thousands of people in the gaming industry out of work overnight. And there is a legitimate concern that addicted players will not simply stop, they will move to illegal, unregulated platforms that are now harder to monitor than the licensed ones that just got shut down. These are not small objections.

rajeshsharma1049@gmail.com



### THE WALL

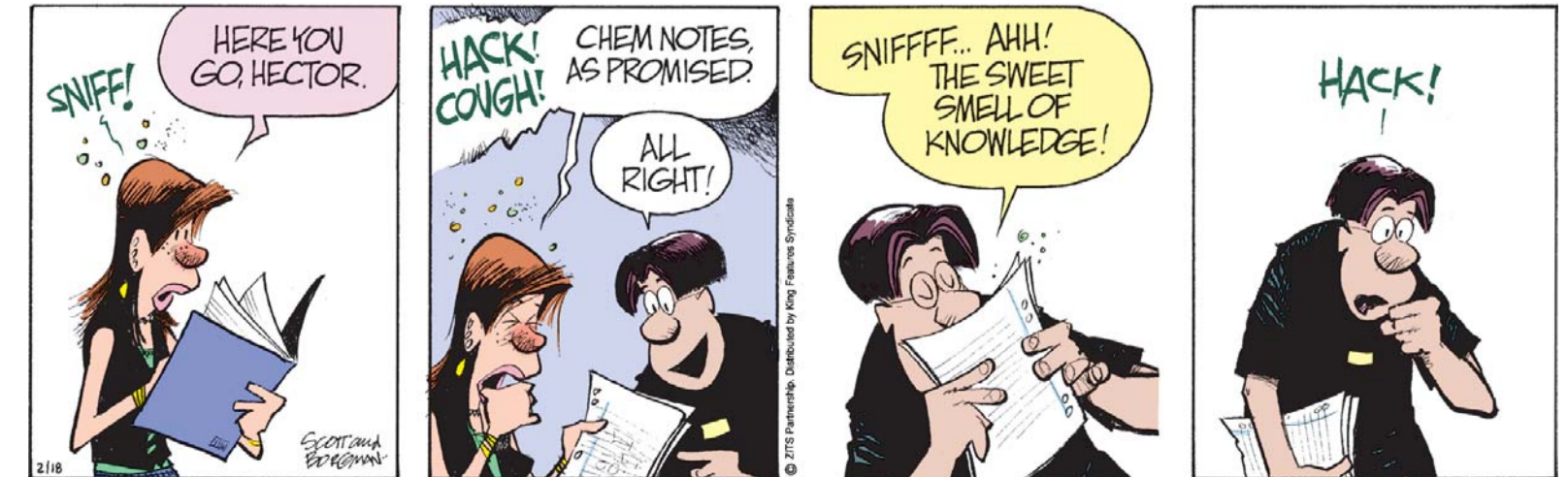


### BABY BLUES



By Rick Kirkman & Jerry Scott

### ZITS



By Jerry Scott & Jim Borgman









# केन्द्रीय जल आयोग यमुना जल पाइप लाइन की संयुक्त डीपीआर शीघ्र अपलोड करेगा

## मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिल्ली यात्रा में केन्द्रीय जल मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।

दो मई है, जिसे सम्मिलित करते हुए डीपीआर को केन्द्रीय जल आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर शीघ्र ही अपलोड करने के बाद, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा डीपीआर की जांच प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के

बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत हथिनीकुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर तक आर्वाइटी यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा अन्य जिलों तक पहुंचाने की परियोजना पर काम किया जाएगा। इस परियोजना से 577 एमसीएम पानी पेयजल आपूर्ति

और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध होगा। ऊपरी यमुना बेसिन में रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ भंडारण परियोजनाओं के निर्माण के बाद राजस्थान को वर्ष के बाकी समय में भी हथिनीकुंड से इसी पाइपलाइन प्रणाली के जरिए जल मिलता रहेगा। किशाऊ परियोजना टोन्स नदी पर

# ‘केरल में मुख्यमंत्री का ऐलान आज होगा’

## कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर विचार मंथन हो चुका है

नई दिल्ली, 13 मई। केरल में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस ने मंथन लगभग पूरा कर लिया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अंतिम निर्णय गुरुवार को घोषित किया जाएगा। जयराम रमेश ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केरल कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के सदस्यों को मंजूरी के बाद पार्टी हाईकमान ने सभी जरूरी विचार-विमर्श पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की आधिकारिक घोषणा गुरुवार को सार्वजनिक रूप से की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री चयन को लेकर पार्टी के भीतर व्यापक स्तर

कांग्रेस आलाकमान ने इस मसले पर केरल में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी चर्चा की थी।

पर चर्चा हुई है। सभी वरिष्ठ नेताओं से राय लेने के बाद अब मामला अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पार्टी नेतृत्व ने एक नाम पर सहमति बना ली है, जिसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को की जाएगी।

मुख्यमंत्री पद की दौड़ में तीन प्रमुख नेताओं के नाम सबसे आगे बताए

जा रहे हैं। इनमें रमेश चेन्नियाला, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं।

राहुल गांधी ने इन नामों पर राय जानने के लिए वीएम सुधीरन, एमएम हसन और के सुधाकरण समेत कई पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से अलग-अलग बातचीत की। मुल्लाप्पल्ली रामचंद्रन से भी फोन पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री चयन को लेकर दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के पूर्व अध्यक्षों से मुलाकात कर राज्य की राजनीतिक स्थिति और जनता के मूड पर चर्चा की।

## नीट 2026 पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट में

नई दिल्ली, 13 मई। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित परीक्षा नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने नीट 2026 के

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने नेशनल टैरिफिंग एजेंसी (एनटीए) की विफलता को चुनौती दी।

आयोजन में नेशनल टैरिफिंग एजेंसी (एनटीए) की प्रणालीगत विफलता को चुनौती दी है। एफएआईएमए ने मामले की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा कराने और इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज की अध्यक्षता में कराने की मांग की है।

याचिका में नीट 2026 देवारा कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की मांग की गई है। याचिका में मांग की गई है कि जब तक नई स्वतंत्र परीक्षा संस्था औपचारिक रूप से नहीं बन जाती, तब तक इसी न्यायिक समिति की निगरानी में नीट 2026 की देवारा परीक्षा कराई जाए।

## बुधवार को आंधी-तूफान ने यूपी में तबाही मचाई

### आंधी-पानी की चपेट में आने से प्रदेश के नौ जिलों में 62 लोगों की जान गई

लखन, 13 मई। प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। तेज हवाओं के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। आंधी-पानी की चपेट में आने से अलग-अलग जिलों में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान और टीन शूट उड़ गए, वहीं फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा।

तेज बारिश और धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया, बनें बनें लोगों में भदोही में 11, मिर्जापुर में 6, सीतापुर में 2, कानपुर मंडल में 14, प्रयागराज में 9,

## ‘पेड़ों को बचाने ...

कि वर्तमान में हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 9 मार्च को एक विशेष समिति का गठन किया था, जो प्रदर्शनों के माध्यम से राज्य सरकार को समझें और उनका हल बतायें और हो सके तो कानून बनाने का भी प्रस्ताव रखें। उल्लेखनीय है कि इस समिति में राजस्व विभाग, विधि विभाग और वन विभाग के मंत्रियों समेत, विधि विभाग के प्रमुख सचिव, हाईकोर्ट के अतिरिक्त महाअधिवक्ता और अधिवक्ता कुणाल विश्वनोई को सदस्य बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिये कि याचिकाकर्ता श्री ब्रामेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था' भी इस समिति को सहयोग करने के लिये स्वतंत्र है। इस आदेश के साथ ही अदालत ने इस याचिका का निस्तारण कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले का निस्तारण करते हुए टिप्पणी भी की कि खेजड़ी का पेड़ एक दुर्लभ पेड़ है, जिसकी पर्यावरण की दृष्टि से गहरी महत्ता है। यह पेड़ कई वर्ष किलोमीटर के क्षेत्र में एक ही पेड़ उता है, फिर भी सोलर प्लांट के लिये इसे काटा जा रहा है, जो एक चौकाने वाली चीज है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाई समिति इस पेड़ के महत्व को समझेगी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि शायद 1730 में दिये गये प्रमाण की तरह ही आज का सत्ता पक्ष भी ऐसा ही निर्णय लागू करेगा।

आधुनिक महान-शक्ति प्रतिस्पर्धा अब दुश्च प्रभाव की तुलना में धैर्य की अधिक महत्व देती है। आर्थिक मजबूती, औद्योगिक गहराई, तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और संस्थागत निरंतरता अब सैन्य शक्त के समान महत्वपूर्ण हैं। ऐसे मामलों में, नेतृत्व शैली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है।

## ट्रंप बीजिंग पहुंचे, उपराष्ट्रपति ने स्वागत किया

बीजिंग, 13 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को चीन पहुंचे। हालांकि, उनकी यात्रा को शुरूआत से ही एक कूटनीतिक संकेत चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिंफिंग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे। ट्रंप और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया। ट्रंप के साथ उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी मौजूद थे।

बीजिंग एयरपोर्ट पर ट्रंप के स्वागत के लिए विशेष समारोह आयोजित किया गया। अमेरिकी और चीनी अधिकारियों के अलावा, सैंकड़ों युवाओं को भी वहां तैनात किया गया था, जिन्होंने दोनों देशों के झंडे लहराकर अमेरिकी राष्ट्रपति का अभिवादन किया। समारोह में सैन्य बैंड और औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर भी शामिल रहे।

जिनपिंग का एयरपोर्ट पर मौजूद होना चीन की ओर से एक प्रतीकात्मक

चीन के राष्ट्रपति शी जिंफिंग को एयरपोर्ट पर ट्रंप का स्वागत नहीं करने को कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।

कूटनीतिक संदेश माना जा सकता है। आमतौर पर ट्रंप के विदेशी दौरों में मेजबान देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद उनका स्वागत करते रहे हैं। हाल के महीनों में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में उनका स्वागत शीप नेतृत्व ने ही किया था। यह ट्रंप की 2017 के बाद दूसरी चीन यात्रा है। उस समय भी उनका स्वागत शीप पर हुआ था, जबकि 2009 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के चीन दौरे के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिंफिंग स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे थे।

## क्या सोनिया ...

गांधी द्वारा केरल पार्टी के विभिन्न नेताओं से परामर्श करने के एक दिन बाद उठाया गया। इस बीच, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूपीएमएल) ने अपने राज्य अध्यक्ष पनकड सैयद सादिक अली शिहाब ठंगल को मुख्यमंत्री के चयन के बाद कांग्रेस सरकार को समर्थन देने का अधिकार दे दिया है।

## विजय ने ...

लिए मतदान करायी गया। तमिलनाडु की टीवीके सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विश्वास मत के दौरान सरकार को 144 सदस्यों का समर्थन मिला और बहुमत हासिल कर लिया है।

## यूपी की भांति बंगाल में ...

मंत्रों ने अस्पताल की स्थिति पर नाराजगी जताई, जहाँ घायल लोग भर्ती थे। उन्होंने मरीजों के वार्ड में गंदगी और कचरे की ओर इशारा किया और तुरंत सफाई का आदेश दिया।

नई सरकार काम काज में सक्रियता दिखाकर लोकप्रियता पाने की कोशिश नहीं छोड़ रही है। नए मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी पहले ही बुलडोजर दावा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं।

टॉपसिया इलाके में भी इसी तरह की कार्रवाई शुरू की गई, जहाँ कई लेदर फैक्ट्रियाँ हैं। बंगाल में अवैध निर्माण फैल गए हैं, जो लोगों के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा बन गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इन इमारतों को अनुमति देने में नगर निगम के कुछ अधिकारियों को कट मनी दी गई थी।

आग उस लेदर फैक्ट्री में लगी, जहाँ सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था। फैक्ट्री के मालिक और प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है। ये इमारतें शहरी मामलों के पूर्व मंत्री फिरोज हकीम के समय में अनुमति के बाद बनी थीं। नई सरकार ने पूरे राज्य में अवैध निर्माणों का विस्तृत ऑडिट करने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी इमारत को खड़ा न रहने देने

## आखिर ... सीबीएसई 12 वीं का परिणाम घोषित

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेपर' पी.डी.एफ. फॉर्मेट में सीकर के एक मित्र से मिला था। चूंकि वह पहले से ही मैडिकल पढ़ रहा था, उसे 'गैस पेपर' की आवश्यकता नहीं थी। उसने इसे अपने पिता को भेज दिया जो हॉस्टल चलाते हैं। वह जानता था कि वे जल्दी सोते हैं, लेकिन उसने संदेश भेजा कि अगर हॉस्टल में कोई नीट दे रहा है, तो यह पेपर मददगार हो सकता है। सुबह में, उसके पिता ने यह पेपर चार लड़कियों को देने की कोशिश की, जो परीक्षा दे रही थी। लेकिन वे पहले ही परीक्षा केन्द्र के लिए जा चुकी थीं। जिज्ञासा के चलते, उन्होंने इसे एक केमिस्ट्री टीचर को भी दिखाया, जिसे वे जानते थे।

टीचर ने इसे नीट के पेपर से मिलाया और पाया कि 108 सवालों में से 45 बिल्कुल मेल खा रहे थे। केमिस्ट्री टीचर ने फिर बायोलाजी के एक सहकर्मी से यह जांच कराई और उन्हें आश्चर्य हुआ कि 204 सवालों में से 90 सवाले मेल खा रहे थे।

'गैस पेपर' का स्ट्राइक रेट आश्चर्यजनक था - कुल 135 सवाल असली पेपर से मैच कर रहे थे। हॉस्टल मालिका और केमिस्ट्री टीचर ने स्थानीय पुलिस से संपर्क करने का निर्णय लिया। उन्हें हैरानी हुई कि सीकर पुलिस ने मामला दर्ज करने या जांच करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि अगर दोनों परीक्षा खत्म होने के बाद मामला दर्ज करना चाहते हैं, तो उनके इरादों पर शक हो सकता है। पुलिस ने तर्क दिया कि शायद वे परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं।

'गैस पेपर' का स्ट्राइक रेट आश्चर्यजनक था - कुल 135 सवाल असली पेपर से मैच कर रहे थे। हॉस्टल मालिका और केमिस्ट्री टीचर ने स्थानीय पुलिस से संपर्क करने का निर्णय लिया। उन्हें हैरानी हुई कि सीकर पुलिस ने मामला दर्ज करने या जांच करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि अगर दोनों परीक्षा खत्म होने के बाद मामला दर्ज करना चाहते हैं, तो उनके इरादों पर शक हो सकता है। पुलिस ने तर्क दिया कि शायद वे परीक्षा रद्द करवाना चाहते हैं।

## सीबीएसई 12 वीं का परिणाम घोषित

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नई दिल्ली, 13 मई। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस वर्ष कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहे, जो पिछले साल के मुकाबले 3.19 प्रतिशत कम है। परीक्षा परिणाम में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है।

बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 17,80,365 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 17,68,818 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 15,07,109 विद्यार्थी सफल घोषित किए गए। पास प्रतिशत में 3.19 प्रतिशत की कमी आई, जो 2025 के 88.39 प्रतिशत से घटकर 2026 में 85.20 प्रतिशत हो गया।

## मुलायम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करेगी, ताकि मृत्यु का कारण पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांचकर्ता के अनुसार, शरीर पर चोट के निशान नहीं पाए गए।

प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे। वे फेफड़ों में रक्त के थक्के का इलाज करा रहे थे। जब सुबह उनकी स्थिति बिगड़ी और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, तो उनके परिवार के सदस्य उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल ले गए।

इस वर्ष कुल 85.20 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे, जो गत वर्ष से 3.19 प्रतिशत कम है।

सीबीएसई के अनुसार लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86 रहा, जबकि लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13 प्रतिशत लड़कों के लड़कियों ने 6.73 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया।

## तमिलनाडु में ज्योतिषी की ओएसडी पर नियुक्ति रद्द

चेन्नई, 13 मई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के राजनीतिक सलाहकार के रूप में राज्य सरकार द्वारा विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए रिकी रतन पंडित वेनिवेल के भारी विरोध के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विजय के निजी ज्योतिषी माने जाने वाले रिकी रतन पंडित वेनिवेल को हाल ही में तमिलनाडु वैत्रि कडवम (टीवीके) ने पार्टी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया था। विजय के मुख्यमंत्री पद संभालने के पश्चात तमिलनाडु सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रभाग में विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

## ट्रंप व शी की ...

औपचारिक संरचना पर उनका नियंत्रण है। पार्टी, नौकरशाही, सैन्य और औद्योगिक प्रणाली अंततः एक ही रणनीतिक दिशा में चलती हैं, क्योंकि सत्ता संस्थागत रूप से केन्द्र से नीचे की ओर प्रवाहित होती है।

ट्रंप की प्रणाली अलग तरीके से काम करती है। उनका प्रभाव संस्थागत नियंत्रण पर कम और राजनीतिक प्रभुत्व, व्यक्तिगत निष्ठा, अनौपचारिक पहुंच और व्यक्तिगत संबंधों पर अधिक निर्भर करता है। शी संस्थाओं के माध्यम से अधिक का प्रयोग करते हैं और उन्हें वे ही नियंत्रित करते हैं। ट्रंप उन व्यक्तिगतों के माध्यम से अधिकार का प्रयोग करते हैं, जिन्हें वे प्रभावित करते हैं। यह अंतर निर्धारित करता है कि दोनों शक्तियाँ संकटों में कैसे काम करती हैं और राजनीति का पालन कैसे करती हैं।

ट्रंप की राजनैतिक समझ जल्दी-जल्दी बदलने वाले चक्रों पर काम करती है, जैसे मोडिया चक्र, मतदान चक्र, बाजार प्रतिक्रियाएँ, शिखर कूटनीति भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेजों से नौकरी हासिल की है। मामलों में फागी में तैनात स्कूल व्यवस्थाता अनिता चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामलों का खुलासा हुआ।

## बाबूलाल कटारा की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पूछताछ पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उसकी रिमांड अवधि को बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कटारा की रिमांड अवधि को 16 मई तक बढ़ाते हुए डामोर को जेल भेज दिया। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कटारा ने कृषि विज्ञान प्राध्यापक भर्ती का प्रश्न पत्र साठ लाख रूपए में शेर सिंह मीणा को बेचा था। इसके बाद शेरसिंह ने मोटे